





### सीएम योगी कर सकते हैं महाकुंभ मेले में बने केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) विजन और मार्गदर्शन के मुताबिक प्रयागराज। पीएम मोदी के दौर से मेला प्राधिकरण और अन्य सभी पूर्व सीएम योगी प्रयागराज में विभाग महाकुंभ की तैयारियों में



निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। इस दौरान वह अलोपीबाग फ्लाई ओवर, 6 लेन गंगा सेतु, गंगा रिवर फ्रंट रोड और शिवालय पार्क का भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही वह महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को करेंगे संबोधित कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। प्रयागराज विश्व से सबसे बड़े मानवीय सामगम और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 का साक्षी बनने जा रहा है। दुनिया के कोने-कोने से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री महाकुंभ को दिल से बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। उनके पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्यरत हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रयागराज आ रहे हैं। इस अवसर पर वो मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय हॉस्पिटल और खोया पाया केंद्र का उद्घाटन व अन्य निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी करेंगे। महाकुंभ 2025, 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होगा। इसके पहले महाकुंभ मेला नगरी के साथ-साथ प्रयागराज शहर में भी कई स्थाई व अस्थायी निर्माण कार्य हो रहे हैं। मेला प्राधिकरण के साथ-साथ, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, राज्य सेतु कई अंतिम दौर में हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ स्वयं महाकुंभ के इन निर्माण कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करने प्रयागराज आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पूर्व सीएम योगी का प्रयागराज दौरा संभावित है। इस अवसर पर वो मेला क्षेत्र में बन रहे केंद्रीय हॉस्पिटल, खोया-पाया केंद्र और सेक्टर-1 में बन रहे पब्लिक एकमोडेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह महाकुंभ क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में बने पुलिस लाइन में महाकुंभ के लिए आए पुलिस कर्मियों को भी संबोधित करेंगे।

### महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार से मिलेंगे 2100 करोड़ रुपये, 1050 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। दिव्य, भव्य, डिजिटल महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। योगी सरकार पहले ही 5435 करोड़ से अधिक की



व्यवस्था कर चुकी है। केंद्र से विशेष सहायता मिलने के बाद महाकुंभ का आयोजन और ज्यादा सुव्यवस्थित और सुरक्षित होगा। प्रयागराज में आगामी जनवरी माह से शुरू हो रहे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सामगम 'महाकुंभ-2025' के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा 'उपहार' भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करते हुए पहली किस्त

के रूप में 1050 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के मध्य निर्धारित है। महाकुंभ मेला के सकुशल आयोजन के लिए भारत सरकार इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों, जिसमें लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, सेतु निगम, पर्यटन विभाग, सिंचाई, नगर निगम प्रयागराज, द्वारा विभागीय बजट मद से 1636.00 करोड़ रुपए की 125 परियोजनाओं को क्रियान्वित कराया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधायें, जिसमें रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अण्डरब्रिज, सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य, नदी के किनारे कटाव निरोधक कार्य सहित इंरलॉकिंग सड़क मार्ग, रिवर फ्रंट का निर्माण, स्मार्ट सिटी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के समन्वय से प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त चौराहों का थीम बेस्ड सौन्दर्यीकरण, आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग इत्यादि कार्य एवं श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन एवं नगर निगम, प्रयागराज के समन्वय से शहर की साफ-सफाई एवं स्वच्छता के लिए उच्च कोटि की व्यवस्था की जा रही है। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एवं शहर को 100 प्रतिशत सीवेज ट्रीटमेंट से आच्छादित किया जा रहा है।

### अध्यक्ष के आदेश पर 2021 में ही निरस्त हो चुकी थी नोटिस, छात्र नाराज; फूँका पुतला

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) वाराणसी। यूपी कॉलेज की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक पत्र जारी किया है। इसके अनुसार, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यूपी कॉलेज



कि हम यूपी कॉलेज के छात्रों के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड को सरकार जल्द से जल्द बैन कर शांति स्थापित करे। छात्रसंघ अध्यक्ष प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ है। प्रशासन को जारी नोटिस वर्ष 2021 में ही निरस्त किया जा चुका है। बोर्ड के लोगों ने अफवाहों पर ध्यान न देने की भी बात कही है। कुछ दिन पूर्व उदय प्रताप कॉलेज की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके विरोध में यूपी कॉलेज के छात्रों ने विरोध दर्ज कराते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी। वहीं, इस मामले को लेकर अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने भी अपनी नाराजगी जताई। छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला दहन किया है। वहीं, यूपी कॉलेज में मौजूद मजार पर वक्फ बोर्ड द्वारा अपना दावा छोड़ने के बाद प्रिंसिपल डॉ. डीके सिंह ने सभी छात्रों से सौहार्द बरतने की अपील की है। छात्र नेता शिवम तिवारी ने कहा और यूपी कॉलेज का स्थापना 1909 में हुई थी। इस पर ध्यान दिया जाए तो यूपी कॉलेज की जमीन बोर्ड की कैसे हो सकती है। ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली समिति अंजुमन इतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यूपी कॉलेज प्रशासन को जारी नोटिस वर्ष 2021 में ही निरस्त किया जा चुका है। इसलिए कोई भी किसी भी के उकसावे में न आए और अफवाहों पर ध्यान न देकर शांतिपूर्ण तरीके से रहे इस संबंध में उन्होंने यूपी कॉलेज स्थित मस्जिद के संबंध में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से पत्राचार कर वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी



# NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

## सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी

फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड

कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है।

रिलीफ एजेन्सी N.G.O., डिफेन्स सर्विसेज फायर सर्विस आर्डिनेन्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, माइनिंग इण्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम कम्पनी, फूड इण्डस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल, टावर कम्पनी, इलेक्ट्रानिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर सेफ्टी के जानकारों को बहुत अधिक मौका मिलता है

नोट: फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश-विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।

(वरिष्ठ आई.पी.एस.) श्री अविनाश चन्दा

महानिदेशक

अविनाशमन सुरक्षा एवं आपात सेवा उत्तर प्रदेश



Visit us at [www.nainiiti.com](http://www.nainiiti.com) Call: 9415608710, 7459860480





# प्रदेश आस/पास



# भारत

## वाराणसी, रायबरेली

### व्यापारी मनोज पांडेय होटल में प्रेसवार्ता करके अपनी सफाई प्रस्तुत की

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। व्यापारी मनोज पांडेय बजरंगदास के कथित नोटों की गिनती करते हुए वायरल वीडियो के संदर्भ में मनोज पांडेय ने आज मांग पर सभी अभिलेख उसके समझ प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक कुछ एक सरकारी संस्था द्वारा मुझसे कागजात मांगे गए हैं। मैंने सभी करूंगा की इस तरह मुझे जीवन के भय में डालने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिससे भविष्य में कोई किसी अन्य व्यापारी को जीवन भय में डाल सके। उन्होंने



शहर के एक होटल में प्रेसवार्ता करके अपनी सफाई प्रस्तुत की। उन्होंने कहा की जो पैसा वीडियो में दिख रहा है वह मेरा है और उसके कागजात मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारी हूँ और पैसे का लेनदेन व्यापार में करना पड़ता है। मेरे पास बैंक के स्टेटमेंट हैं और मैं बड़ी रकम आयकर के रूप में सरकार को देता हूँ। मेरा सारा लेनदेन सही और कानूनी है। जो भी एजेंसी जांच करेगी मैं उसके साथ सहयोग करूंगा और उसके कागजात उन्हें दिखाएँ हैं। भविष्य में भी जो भी जांच होगी मैं उसमें से सारे अभिलेख प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने कहा कि जिस चैनल और जिस पत्रकार ने नोट गिनते हुए मेरा वीडियो वायरल किया है उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। इस वीडियो से मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरा अपहरण भी हो सकता है मुझसे भविष्य में रंगदारी भी मांगी जा सकती है। इसकी शिकायत में संबंधित अधिकारियों से करूंगा और यह भी अनुरोध

### ग्रामीण बाजारों में शीघ्र लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। पंडित दीनदयाल विकास योजना के चयनित ग्रामों में ग्रामीण बाजारों का चयन करते



योजना के अंतर्गत ग्रामीण बाजारों में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन हेतु बाजारों के चयन से संबंधित आवश्यक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक यूपीनेडा से इस योजना से संबंधित अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। परियोजना निदेशक ने बताया कि पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्र में समस्त विकास खंडों से एक या दो मुख्य बाजारों में प्राथमिकता पर मुख्यमंत्री समग्र हुए 139 अदद सोलर लाइट अधिष्ठापित की जाएगी। परियोजना निदेशक ने बताया कि अभी तक 204 ग्रामीण बाजारों का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। जिलाधिकारी ने उपस्थित खंड विकास अधिकारियों सहित डीपीआरओ को निर्देशित किया कि योजना को धरातल पर शीघ्र लागू कराया जाए। जिससे की योजना का लाभ जन सामान्य को मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

### साइंस सिटी का भ्रमण कर तकनीकी दुनिया में खोए बच्चे

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। सवाना के जंगलों, पहाड़ों के घने जंगलों में हलचल मचाने वाले जंगली जानवरों को देखने से लेकर लायन सफारी का आनंद



अमावां ब्लॉक के बच्चों ने साइंस सिटी में लिया। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता क्विज प्रतियोगिता में विजयी रहे बच्चों को लखनऊ की एक्सपोजर विजिट करके जानी। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले क्लास 6 से 8 तक बच्चों को मंगलवार को आंचलिक केंद्र का भ्रमण कराया गया। एक्पोजर विजिट की बसों को हरी झंडी दिखाते

### जिलाधिकारी ने तहसील सलोन का किया निरीक्षण

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने तहसील सलोन का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील



के सभी पटलों के अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कमी मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। कहा कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। फाइलों को एक पटल पर ज्यादा दिनों तक ना रोका जाए। जिससे लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। राजस्व के मामलों में दोनों पक्षों की बातें को रिकार्ड कक्ष में सुव्यवस्थित रखा जाए। जिससे की आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः सत्यापन हो सके। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाए और उनका गुणवत्तापरक निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जाए। तहसील न्यायालय से संबंधित वादों को शीघ्र निस्तारित कराया जाए। इस अवसर पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

### जिलाधिकारी ने राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालपुर का किया औचक निरीक्षण

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता



माथुर ने राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालपुर सलोन का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया। तदोपरान्त पठन-पाठन, पुस्तकालय, छात्रावास, खानपान, प्रयोगशाला व सुरक्षा आदि संबंधी मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अध्ययनरत विद्यार्थियों से शिक्षा के विभिन्न

# आधुनिक गैरह हाउस

- वाटर प्रूफ शेड
- पार्किंग की सुविधा
- मन्दिर की सुविधा
- सी.सी.टीवी.
- छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
- 45000 sq. feet. एरिया
- हरे-भरे वातावरण
- AC कमरा (VIP)

CALL: 9519313894, 9415608783, 9415608710

आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, औद्योगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज









# ADHUNIK TUTORIALS

" FOR THE STUDENTS, FROM A STUDENT "

FOR CLASSES 1<sup>st</sup> 5<sup>th</sup>  
(ADMISSION OPEN)

## FACILITIES

- Air Conditioned & Well Furnished Classroom
- Water Cooler Available
- Hygienic Washrooms
- CCTV for Safety Purposes
- In Campus Parking



**Dr. (Er)Puneet Arora (HON. DIRECTOR)**  
(B.Tech, M. Tech, MBA, Ph.D)  
Awarded with ' Young Scientist & Best Teachers, Author of Many Books Chapters, Research Paper, Patent & Trademarks

### Ms. Nilanjana Arora (Assistant Director)

- Ex. Student of Bethany Convent School, Bishop Johnson School & College, Girl's High School & College
- Pursuing B.Tech
- Awarded by TCS
- Certification in the Field of Web Development and Machine Learning .



### Ms. Riya Arora (Counsellor)

- Ex. Student of Delhi Public School.
- Subject Topper of Delhi Public School
- Pursuing LLB from University of Allahabad .



Address: B-Block, ADA Colony, Mtek Campus, Naini, Prayagraj .

Contact :- Call and Whatsapp: 8542919234

## मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए - शैलेन्द्र मिश्रा

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्रा ने अपने

जिसमें मैथिली भाषा को मोदी सरकार ने संविधान में पास कराया इसके लिए धन्यवाद किया

कि मैथिली भाषा की पढ़ाई सीबीई सी बोर्ड एवं सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक कि पढ़ाई सुरु करें न्स् बी पी ए सी एवं सरकारी संस्थानों में मैथिली भाषा को लागू कराए और काफी मांग रखा गया सांसद जी सभी बातों को नोट किए और कहा बहुत जल्द इसका पत्र बनाकर भारत सरकार एवं विहार एवं दिल्ली सरकार को भेजा जायेगा। प्रतिनिधि मंडल में शैलेन्द्र मिश्रा अध्यक्ष दिवा कांत झा उपाध्यक्ष प्रेम शंकर झा महासचिव सुमित झा सचिव राज मंडल सचिव पंडित रवीन्द्र मिश्रा और कई सदस्य उपस्थित हुए।

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। नोएडा दिल्ली हाईवे पर दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों की गिरफ्तारी के लिए एस के एस योगी

हैं और एसकेएम न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह करता है। एसकेएम उत्तर प्रदेश के



आदित्यनाथ सरकार की कड़ी निंदा करता है। पुलिस ने सौ से अधिक महिलाओं सहित सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया है और उन्हें विरोध स्थल से जबरन हटा दिया है। यह शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन

बनी आम सहमति का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग दोनों यूपी प्रशासन के अहंकार का विरोध किया, जिसमें यूपी के मुख्य सचिव को किसान नेतृत्व के साथ चर्चा करने और मांगों को हल करने के लिए 7 दिन का समय मांगा गया था। उनके अनुरोध के अनुसार, किसानों ने संघर्ष का स्थान अंबेडकर पार्क के दलित प्रेरणा स्थल पर स्थानांतरित कर दिया था और रात-दिन धरना कर रहे किसानों को बलपूर्वक हटा दिया गया। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों को प्रभावित करने वाली परियोजना का उनके भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से जारी है। 2008, 2011 और 2012 के दौरान इस संघर्ष के तहत पुलिस गोलीबारी में छह किसान शहीद हुए थे। इस

परिप्रेक्ष्य में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए 2 सरकार किसानों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम) बनाने के लिए मजबूर हुई थी। लेकिन 2014 में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत एनडीए 1 सरकार एलएआरआर अधिनियम 2013 को अमान्य करने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले आई। भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले देश भर में किसानों के संघर्ष के कारण वे कानून बनाने में विफल रहे। उत्तर प्रदेश सहित भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने एलएआरआर अधिनियम 2013 का उल्लंघन करने के लिए राज्य भूमि कानून लाए थे। लेकिन किसान अपने वास्तविक भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रख

रहे हैं और ग्रेटर नोएडा परियोजना से प्रभावित किसानों का संघर्ष इस देशव्यापी संघर्ष का हिस्सा है। भूमि के सर्किल रेट में 2017 से संशोधन नहीं किया गया है। यूपी में किसानों को रोजगार, पुनर्वास और पुनर्वास सहित एलएआरआर अधिनियम 2013 द्वारा सुनिश्चित पर्याप्त, वैध मुआवजे और लाभों से वंचित किया गया है। ग्रेटर नोएडा परियोजना से प्रभावित किसान विकसित भूमि का 10% वापस पाने, भूमिहीन किसान परिवारों के लिए रोजगार, पुनर्वास और पुनर्वास के अलावा मुआवजे के रूप में सर्किल रेट की 4 गुना दर पाने के हकदार हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार परियोजना प्रभावित किसानों के इन वैध अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ग्रेटर नोएडा के किसानों के अलावा, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों किसान परिवार भी प्रभावित हैं।



प्रतिनिधि मंडल के साथ दरभंगा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर से उनके दिल्ली आवास कावेरी में किया गया मुलाकात एवं ज्ञापन दिया।

एवं मैथिली भाषा को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि जब मैथिली भाषा को संविधान की मान्यता मिल गया तो आप भारत सरकार एवं बिहार सरकार को पत्र लिखिए

